RNI NO. - CHHHIN/2011/38292

13 वर्ष निर्भीक पत्रकारिता के

अब 14 वें वर्ष की ओर

पाठकों/दर्शकों का असीम स्नेह

Bharatsamman.com Bharat samman Bharat Samman

हो जाओ सावधान

वर्ष-13 अंक-252 अम्बिकापुर, शुक्रवार, 22 मार्च 2024 कुल पृष्ठ-4 मूल्य-1.00 रू.

सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार

शराब घोटाले में ईडी का एक्शन

नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराह घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। दो घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम को अरेस्ट किया है। गुरुवार को ही सीएम द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी जाए। लेकिन तब कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और अब उस झटके के बाद आम आदमी पार्टी को दूसरा झटका भी लग गया है।

बताया जा रहा है कि कल यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ही राहत के लिए वो याचिका दायर की गई है। लेकिन तब तक सीएम के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उनकी गिरफ्तारी होना जमीन पर सभी समीकरणों को बदलने वाला है। इस समय लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, ऐसे में उस बीच ईडी का ये एक्शन मायने रखता है। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। मांग की गई है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत दी जाए। वैसे आम आदमी पार्टी तो चाहती थी कि आज गुरुवार को ही देर रात इस मामले में सुनवाई हो जाए, लेकिन अब कल यानी कि शुक्रवार को ये बड़ी सुनवाई होने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु की सीएम जय ललिता, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कर्नाटक से पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा को भी ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था। अब उसी लिस्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। यहां ये समझना जरूरी है कि ईडी की जो चार्जशीट सामने आई है,उसमें एक बार नहीं कई बार अरविंद केजरीवाल केक नाम का भी जिक्र किया गया है। अब नाम इसलिए है क्योंकि जांच एजेंसी को पता चला है कि जिस समय दिल्ली की नई शराब नीति बनाई जा रही थी, तब केजरीवाल का हर उस शख्स से संपर्क था जो इस समय इस घोटाले में फंसा हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता के अकाउंटेंट बुचीबाबू से जब पूछताछ हुई थी, तब उनकी तरफ से भी सीएम का नाम लिया गया था। उन्होंने दो टूक कहा था कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच एक राजनीतिक समझ चल रही थी।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, कहा-जो भाजपा में नहीं जाएंगे, वो जेल जाएंगे

शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि जो भाजपा में नहीं जाएंगे, वो जेल जाएंगे. तानाशाही चरम पर है. सनद रहे, अहंकार ईश्वर का भोजन है. हम सब तानाशाही के विरुद्ध एकजुट हैं. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है. इस गिरफ़्तारी के खिलाफ कल रायपुर में आप का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा. अंबेडकर चौक पर पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे. प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से भी आप कार्यकर्ता शामिल होंगे.

पिनाराई विजयन ने गिरफ्तारी को बताया आपत्तिजनक

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बेहद आपत्तिजनक है। यह कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया के स्तर पर विपक्षी आवाज को बंद करने के प्रयास का हिस्सा है।

विपक्ष के नेताओं को जनता से दूर करना चाहती है भाजपाः अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद।% उन्होंने कहा कि भाजपा जानती है कि वो फिर दुबारा सत्ता में नहीं आनेवाली, इसी डर से वो चुनाव के समय, विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है, गिरफ्तारी तो बस बहाना है। पूर्व सीएम ने कहा कि ये गिरफ्तारी एक नयी जन-क्रांति को जन्म देगी।

हम केजरीवाल सरकार के साथ खड़े हैंः तेजस्वी यादव

वहीं, राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय भाजपा जांच एजेंसियों एवं अन्य संवैधानिक संस्थानों की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को केंद्र सरकार ने तार-तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं। जैसा की हम सब ने पटना व मुंबई से खुल कर ऐलान किया था - हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़ कर जीतने वाले लोग हैं।

हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया

इससे पहले गुरुवार को दोपहर 2.30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने कोर्ट से ये भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए श्वष्ठ जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बार-बार समन भेजने को लेकर श्वष्ठ को तलब किया। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए।

जेल जाने पर लालू ने राबड़ी देवी को बना दिया था सीएम

बात साल 1996 की है। बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे। उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा। सीबीआई ने लालू यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सीबीआई ने जून, 1997 को लालू यादव और अन्य 55 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। लालू यादव पर किसी भी वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ऐसे में जेल जाने से पहले लालू यादव ने अपनी कुर्सी के लिए उत्तराधिकारी खोजना शुरू किया। लालू यादव ने अपनी करीबी नेताओं से सलाह-मशवरा करके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी दी थी। उस वक्त राबड़ी देवी न तो चुनाव लड़ी थीं, और ना ही राजनीति में थी। उस वक्त राबड़ी देवी ने सत्ता तो संभाल ली, लेकिन पर्दे के पीछे से जेल में बंद लालू यादव ही सरकार चलाते रहे। बाद में 1997 से 2005 तक राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही थीं।

क्या सुनीता केजरीवाल बनेंगी सीएम?

केजरीवाल के जेल जाने पर सवाल उठने लगा है क्या सुनीता केजवाली सीएम बनेंगी। दरअसल बीजेपी लंबे समय से ये दावा करती आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो वह सरकार बचाने के लिए अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे, जैसे लालू यादव ने जेल जाने पर राबड़ी देवी को बनाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आप नेता आतिशी ने मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगें और जेल से ही सरकार चलाएंगे।

क्या जेल से चल सकती है सरकार?

जेल जाने पर बिना आरोप सिद्ध हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। हालांकि जेल से सरकार चलाने में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर ली लालू यादव हों या हेमंत सोरेन, इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल मुख्यमंत्री का काम सिर्फ कागज पर साइन करना नहीं होता है। मुख्यमंत्री के पास अधिकारियों से मशवरा करना, कैबिनेट मीटिंग, सहित कई काम रहते हैं, जो जेल में रहते हुए संभव नहीं है।

आतिशी बोलीं- भाजपा डरी हुई है

दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा- दो साल से जांच चल रही है। लेकिन एक पैसा भी न सीबीआई को मिला, न ईडी को मिला। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि, मोदी जानते हैं कि उन्हें टक्कर देने वाला एक मात्र अरविंद केजरीवाल ही है। दो सीएम अरेस्ट किए गए। एक पार्टी के खाते सीज किए गए। ये भाजपा का डर दिखाती है।

गोपाल राय बोले- केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली की जनता का अपमान

गोपाल राय बोले- ये संदेश है कि भाजपा के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने आज लोकतंत्र की हत्या की है। ये दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान है। इस देश के संविधान और लोकतंत्र का सम्मान करने वालों को अरेस्ट किया गया है। भाजपा अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके वे आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। विपक्ष को डरा देंगे। तो ये उनकी गलत फहमी है। इसके खिलाफ देश लड़ाई लड़ेंगे।

अरविंद केजरीवाल को टार्गेट करना गलत और असंवैधानिक- प्रियंका गांधी

अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी की ख़बर पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत और असंवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टार्गेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है. राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को. अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िये, उनका डटकर मुक़ाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए - यही लोकतंत्र होता है. मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मक़सद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमज़ोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के ख़िलाफ़ है. देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज़ कर दिये गये हैं, तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है, एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिये गये हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है.

राहुल गांधी ने बोला हमला

वहीं, सीएम केजरीवाल पर ईडी के एक्शन के बाद विपक्षी नेताओं ने केंद्र पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है, जिसका आईएनडीए गठबंधन मुंहतोड़ जवाब देगा।

खरगे ने क्या कहा?

इधर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज का भी मामला उठाया। खरगे ने कहा कि भाजपा को अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का बैंक खाता सीज नहीं किया जाता।

इस सरकार को जाना तय- लालू यादव

क्क के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार के डर में गिरफ्तार ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सरकार को जाना तय है।

संपादकीय

जनसंख्या नियंत्रण : सख्ती भी सहमति भी

स्वातंत्र्योत्तर भारत की सरकार ने आम जन को जब पहली बार 'परिवार नियोजन' शब्द से परिचित कराया, तब अनेक लोगों का कहना था कि क्या अब यह भी सरकार बताएगी कि बच्चे कितने पैदा करने हैं! तब से आज तक सरकार द्वारा परिवार नियोजन संबंधी अनेक पहल की जा चुकी हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के हाल ही के एक ऐतिहासिक निर्णय से यह मुद्दा एक बार फिर से सार्वजनिक बहसों में जीवित हो उठा है। 12 अक्टूबर, 2022 के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए राजस्थान सरकार के सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों के नियम पर मुहर लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, 'राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 का नियम 24(4) गैर-भेदभावपूर्ण है, और संविधान का उल्लंघन नहीं करता। यह संविधान के दायरे से बाहर है, क्योंकि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार का नियम नीति के दायरे में आता है। अतः इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है।' इसका अर्थ हुआ कि राजस्थान सरकार का यह कानून अब पूर्णतः स्थापित हो चुका है, जिसके अनुसार राजस्थान में अब दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला न केवल सकारात्मक है, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय को प्रोत्साहित करता हुआ विकसित भारत के निर्माण में परिवार नियोजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। वस्तुतः ऐसा नियम बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य नहीं है। अन्य कई राज्यों में ऐसी नीतियां पहले से ही लागू हैं। मध्य प्रदेश में 2001 से सिविल सेवा (जनरल कंडिशन ऑफ सर्विसेज) लागू है। तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम का सेक्शन 19(3), 156(2), 184(2) दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करता है। आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1994 में भी यही धाराएं लागू हैं। 2005 के गुजरात सरकार के लोकल अथॉरिटीज एक्ट के संशोधन केअनुसार दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव नहीं लड़ सकते। उत्तराखंड सरकार ने दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला किया था। महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम उन लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करते हैं, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। हरियाणा के पंचायत चुनाव में भी ऐसे ही नियम लागू हैं। जनसंख्या नियंत्रण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर खूब विमर्श होते रहे हैं। जनसंख्या की बात होते ही भारत की तुलना चीन से की जाने लगती है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि 1970 के दशक में भारत में जब परिवार कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसी के आसपास 1979 में चीन ने भी दो बच्चों की नीति को लागू कर दिया था, लेकिन भारत में यह संकल्प बार-बार दुहराया जाता रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत को चीन जैसी कठोर नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि सत्तर और अस्सी के दशक में दुनिया के ये दो बड़े देश जनसंख्या नियंत्रण की ओर बढ़ रहे थे लेकिन यह भी सच है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन भारत से सवा तीन गुना से भी ज्यादा बड़ा देश है। भारत का जनसंख्या घनत्व भी चीन से बहुत अधिक है। चीन में जहां बहुसंख्यक आबादी आज वयस्क हो चुकी है वहीं भारत आज युवाओं का देश है। गैर-बराबरी के ऐसे अनेक बिंदुओं के कारण भारत और चीन के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के सूत्र या प्रतिमान एक जैसे नहीं हो सकते। पिछले कोई दो दशकों में भारत की आबदी लगभग चालीस फीसद बढ़ी है। वर्तमान भारत में लगभग ढाई करोड़ लोगों का हर साल जन्म होता है और नब्बे लाख लोगों की मृत्यु होती है यानी भारत की वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि डेढ़ करोड़ के बीच होनी चाहिए लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। धीरे-धीरे बढ़ता जनसंख्या का यह असंतुलन भारत के लिए समस्या बनता जा रहा है। इसके समाधान स्वरूप परिवार नियोजन को कुछ दशक के लिए लागू करने की बात प्रमुखता से उठाई जाती है। समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ेगा और संसाधनों के अनुरूप आबादी के आधिक्य से संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता जाएगा। ऐसे में सरकारी नौकरियों में दो बच्चों का नियम नीतिगत एवं सामाजिक स्तर पर बड़ा संदेश देने की जरूरी कोशिश प्रतीत होता है। इस प्रकार के विषयों पर सामान्यतः विभिन्न समुदायों के बीच असहमति होती है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कहते हैं जबकि कुछ इसे सामाजिक समानता और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक मानते हैं। यह भी सच है कि कोई भी समाज जैसे-जैसे साक्षर होता जाएगा, परिवार नियोजन जैसी बातें सहजता से स्व-नियमन का हिस्सा बनती जाएंगी। परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण की प्रक्रिया किसी समाज की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन सकती है। इससे सामाजिक समानता, गुणवत्तापूर्ण जीवन-शैली और आर्थिक समृद्धि का द्वार खुलता है। जनसंख्या नियोजन के परिणाम स्वरूप समाज में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में व्यापक सुधार की संभावना दिखाई पड़ती है। मातृत्व स्वास्थ्य, बच्चों की मृत्यु दर और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार की गुंजाइश बढ़ती है। इसके माध्यम से परिवारों के आर्थिक-सामाजिक दबाव को कम किया जा सकता है, जिससे उनकी साक्षरता सहित शिक्षा के स्तर में सुधार हो। जनसंख्या नियोजन से महिलाओं को निर्णायक फैसलों का अधिक नियंत्रण मिलता है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इससे बच्चों समेत परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई पड़ेगा क्योंकि यह उन्हें अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने में मदद करता है। जनसंख्या नियोजन से लघु पारिवारिकता बढ़ती है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संतुलन को सुधारने में मदद कर सकती है। इससे वन्य जीवन को संरक्षित किया जा सकता है, और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संतुलित रूप से हो सकता है। ऐसा करके ही संसाधनों एवं संभावनाओं से परिपूर्ण भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के अपने सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

लालच के चक्कर में पड़ गए लेने के देने : शेयर मार्केट में निवेश के बहाने आरोपी की 40 करोड़ों की ठगी, जांच हुई तो कंपनी ही फर्जी निकली

बिलासपुर। लोगों के पैसे इनवेस्ट कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी 2021 से अब तक लोगों से करीब 35-40 करोड़ की ठगी कर चुका है. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी संख्या में बैंक पासबुक और कागजात जब्त किया है. आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के किम्स हॉस्पिटल के सामने उषालता कॉम्पलेक्स में साईं कृष्णा इन्वेस्टमेट नाम की दुकान है. दफ्तर के संचालक विनायक कृष्णा रात्रे नाम का व्यक्ति जो अपने आप को शेयर मार्केट का ब्रोकर बताता है, वह लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लेता था. आरोपी लोगों से कहता था कि मुझे पैसे दो मैं इसे शेयर मार्केट में लगाकर 5 या 10 के हिसाब से हर महीने फिक्स रिटर्न दूंगा. इस झांसे में आकर बहुत से लोग खाते में पैसा देते थे. वह बाकायदा इनको पैसा रिटर्न भी देता था. साथ ही डेली एक फर्जी हैंडल से सभी को मैनेज करता था. जिसमें निवेशकों का नाम और डेली का रिटर्न लिखा रहता था. इस झांसे में आकर लोग और पैसा इन्वेस्ट करने लगे. कुछ मीडियेटर भी बने. जो बाकी लोगों को अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर इनको ट्रांसफर करने लगे. इस तरह से एक चेन बन गई. अब ये इन पैसों को सर्कुलेट करता था. आपको पैसा लेकर दूसरे को दूसरे का तीसरे को ऐसे ही रोटेट करते रहे. आरोपी ने पैसे का उपयोग अपनी आलीशान जिंदगी के लिए किया. आरोपी लोगों को थाईलैंड गोवा ट्रैवल इन ऑफर देता था. जिसकी वजह से लोग झांसे में आये और लगभग 35 से 40 करोड़ की ठगी का शिकार हो गए. शिकायतकर्ता के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट, इकरारनामा, ऑफर स्कीम खातों के स्टेटमेंट की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि इसके पास सिर्फ गुमास्ता लाइसेंस है और साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी फर्जी है. इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. साथ ही इसके जिन ब्रोकर की लाइसेंस दिखाई है, वह आनंद रात्रे, शानू खान की लाइसेंस है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. जिससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

राजधानी में लगातार बढ़ रहा डायरिया का प्रकोप, मिले 5 और नए मरीज

रायपुर। राजधानी में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है. रायपुर के लाभांडी में डायरिया के 5 और मरीज मिले हैं. इससे अब तक मिले मरीजों की संख्या 25 से ज्यादा पहुंच गई है. नए मरीज मिलने के बाद जोन आयुक्त और प्रशासन के अधिकारी एंबुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे. वहीं लगातार मिल रहे मरीजों से प्रशासन में हड़कंप मच गया है. इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र को अस्थाई अस्पताल बनाया जा रहा है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां के पानी पीने से लोगों में डायरिया हो रहा है. पहले टैंकर से पानी यहां आता था, लेकिन पानी सप्लाई बंद हो गया है. एक-दो हफ्ते से पानी सप्लाई नहीं हो रहा था, इसलिए यहां बोर से लोग पानी पी रहे थे, जिसके कारण डायरिया फैला है. जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि हमारी टीम वहां तैनात हैं. लोगों को इलाज के साथ जागरूक भी किया जा रहा है, जिनको इलाज की जरूरत है. उनको वहीं कैंप बनाकर इलाज मुहैया कराया जा रहा है. 12 लोगों को मेकाहारा में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि लगभग 25 लोगों को डायरिया हुआ है. गंभीर हालात में एक भी नहीं है. सभी की स्थिति नॉर्मल है. कैंप बनाकर वहां इलाज किया जा रहा है. इलाज के लिए टीम तैनात हैं, एम्बुलेंस वहां तैनात किया गया है. डॉ. मिथलेश चौधरी ने कहा कि जैसे की जानकारी मिली थी कि पानी पीने से वहां डायरिया फैल रहा है तो वहां से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है. जब तक पानी का अलग से व्यवस्था वहां निगम की ओर से की गई है. उन्होंने कहा, डायरिया को रोकने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है. इसलिए वहां घर-घर लोगों को अपील किया जा रहा है कि गर्म भोजन करें. साथ ही पानी उबाल कर पीएं.

जोन 4 राजस्व बाजार विभाग ने वार्ड 35 के बड़े बकायादारों पर की सीलबंदी कार्रवाई

शास्त्री बाजार में बकायादार किरायेदार द्वारा बकाया नहीं देने पर दुकान सीलबंद की

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के आदेशानुसार नगर निगम के सभी 10 जोनों के राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन निरन्तर बकाया राजस्व वसूली अभियानपूर्वक की जा रही है. सम्पूर्ण बकाया अदा नहीं करने पर सम्बंधित बड़े बकायादारों के विरुद्ध सीलबंदी, कुर्की की कार्यवाही की जा रही है. इस क्रम में आज नगर निगम जोन क्रमांक 4 राजस्व एवं बाजार विभाग की टीम द्वारा जोन नम्बर 4 के तहत पण्डित रविशंकर शुक्ल वार्ड नम्बर 35 के क्षेत्र में दो वर्षों से नगर निगम के बड़े बकायादार होटल वंश के रूपये 450234 के बकायादार संचालक पर सीलबंदी की कार्यवाही प्रारम्भ की. कार्यवाही के दौरान बकायादार होटल वंश के संचालक ने तत्काल स्थल पर नगर निगम जोन 4 राजस्व एवं बाजार विभाग की टीम को सम्पूर्ण बकाया राशि रूपये 450234 का भुगतान कर दिया एवं स्वयं को सीलबंदी की कड़ी कार्यवाही से सुरक्षित रखा. वहीं आज नगर पालिक निगम जोन 4 राजस्व एवं बाजार विभाग की टीम द्वारा जोन क्षेत्र के तहत शास्त्री बाजार सब्जी मण्डी में दुकान क्रमांक सी 23 के बकायादार किरायेदार रितेश सोनकर द्वारा बकाया राशि 40000 रूपये अदा नहीं किये जाने पर स्थल पर जोन 4 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर नगर निगम राजस्व अधिकारी बलदाऊ वर्मा के नेतृत्व में सीलबंदी करने की कड़ी कार्यवाही की. बकाया राजस्व वसूली अभियान प्रतिदिन आगे निरन्तरता से जारी रहेगा।

लापरवाह सिस्टम ! पशु चिकित्सालय में बढ़ रही डॉक्टरों की मनमानी, ना जिम्मेदारी का ऐहसास, ना अधिकारियों का खौफ, स्टाफ नदारद, दरवाजे पर लटका ताला

तखतपुर। एसडीएम कार्यालय से लगे हुए शासकीय पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों की मनमानी बढ़ती जा रही है. यहां डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ नदारद है. जिसके कारण पशुओं को इलाज के लिए लेकर पहुंच रहे लोग चिकित्सालय में ताला लटकता देख वापस लौट रहे हैं. लिहाजा सही समय में इलाज नहीं मिलने से पशुओं की मौत हो रही है. लंबे समय से शाम वाली ड्यूटी से डॉक्टर गयाब रहते हैं. जबकि चिकित्सालय को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक खोले रखने का निर्देश है.

ऐसे लापरवाह डॉक्टर और स्टाफ को अधिकारियों का भी खौफ नहीं रह गया है. इन सबके बीच समस्या ये भी है कि यदि कोई शख्स यहां आए और उसे ताला लटकता दिखे तो ऐसे में सूचना पटल में जिम्मेदारों का कॉन्टेक्ट नंबर भी कहीं नहीं लिखा है, जिससे किसी से फोन पर बात हो सके.

घंटो करना पड़ रहा इंतजार

ग्राम पंचायत ठकुरीकापा से कमल निषाद अपने पालतू कुत्ते को इलाज के लिए तखतपुर शासकीय पशु चिकित्सालय लेकर आया था. पशु चिकित्सालय बंद होने के कारण वो घंटो इलाज के लिए इंतजार करता रहा. उसने बताया कि उसके पालतू कुत्ते की ताबियत खराब है और वह इलाज कराने आया है. लेकिन अस्पताल में ताला लटकने से उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस संबंध में संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा जेएस तंवर से जानकारी लेने के लिए फोन लगाया गया. लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.

RNI No. CHHHIN/2011/38292
भारत सम्मान NEWS
अम्बिकापुर, शुक्रवार, 22 मार्च 2024

बस्तर में सीएम साय ने भरी हुंकार, कहा- कांग्रेस सरकार में बंद योजनाएं भाजपा सरकार में फिर हुई शुरू, कांग्रेस को नहीं मिल रहे प्रत्याशी

जगदलपुर। 3 महीने में हमने प्रदेश के हित के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे, मोदी जी के पिटारे में अभी प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ बाकी है. यह बातें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बस्तर लोकसभा प्रवास के दूसरे दिन चित्रकोट विधानसभा सीट के बड़ेधाराउर गांव में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कही और पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला.

छत्तीसगढ़ में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सभी को बधाई देते हुए सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ की इंजन को आप सुधार दिए, अब दिल्ली की इंजन को भी ठीक रखना है. सभी वर्ग के लोगों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने काम किया है. कांग्रेस की सरकार आवास योजना को बैन कर दिया, उज्वल योजना बंद कर दिया, इसका सजा उनको मिला. आपने हमें बिठाया तो सभी योजना शुरू हुआ.

सीएम साय ने कहा, कांग्रेस की घोषणा पत्र में बोनस देने का वादा था, लेकिन वो नहीं दिए. हम सरकार में आए, सुशासन दिवस मनाते हुए सबको बोनस दिए, धान का समर्थन मूल्य वादे के हिसाब से दिए. सभी माताओं को महतारी वंदन योजना का पैसा मिला. वित्त मंत्री से हमने आग्रह किया है कि सभी माताओं के खातों में महीने की शुरुआत में पैसा डाल दिया जाए. तेंदूपत्ता के लिए चरण पादुका भी बांटेंगे. ये सभी योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी.

और तेज होगी विकास की रफ्तार

विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव में भी डबल इंजन की सरकार के लिए जनता से समर्थन मांगा. कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए साय ने उसे आदिवासियों का विरोधी और विकास विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया. भाजपा और मोदी सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए जो योजनाएं बनाईं, उसके लिए जो पैसा बस्तर संभाग को भेजा उसे कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया और बस्तरवासियों को मोदी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित कर दिया, लेकिन बस्तर के मेरे भाइयों-बहनों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. अब देश-प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, बस्तर के विकास में कोई भी कमी नहीं होगी. साय ने कहा, भारतीय जनता पार्टी पर आपका विश्वास जम गया है. जो काम 3 महीने में किये हैं आने वाले समय मे भी करेंगे. 500 रुपये सिलेंडर भी देने का वादा बाकी है. बस्तर के सांसद दीपक बैज को मंडल अध्यक्ष ने हरा दिया. लोकसभा के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इनकी नैया में छेद हो गई है. कभी भी डूब सकती है, कोई प्रत्याशी नही बनना चाह रहा है. महेश कश्यप को आप वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिताए, विकास की रफ्तार और तेज़ होगी.

26 कांग्रेस भाजपा में हुए शामिल

इस दौरान लोकसभा चुनाव से पहले 26 लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा. भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा प्रवेश किया. इससे पहले भी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व महिला जिला अध्यक्ष भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं. सभी कांग्रेसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व बस्तर सांसद दीपक बैज के एरिया के थे.

बिल्डर्स को ब्याज सहित रकम वापस करने का निर्देश

व्यवसायिक भूखंड को आवासीय बताकर बेचा

कोरबा। रिस्दी क्षेत्र में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ विकसित किये गए भूखंडों को आवासीय बताकर छलपूर्वक बेचे जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए जिले के एक बिल्डर्स को आवेदक द्वारा दी गई राशि मय ब्याज के वापस किये जाने का आदेश पारित किया है।

जानकारी के अनुसार मेसर्स बुधिया बिल्डर्स एवं डेव्हलेपर्स कोरबा के भागीदार संजय बुधिया द्वारा रिस्दी क्षेत्र में सांई वृंदावन प्रोजेक्ट में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ विकसित किये गए भूखंडों को आवासीय बताकर धोखाधड़ीपूर्वक श्रीमती रजनी ओगरे पति तरूण कुमार ओगरे निवासी एचआईजी-2 हाउसिंग बोर्ड कालोनी बालकोनगर को बेचा गया था। जानकारी होने पर श्रीमती रजनी ओगरे ने अपने अधिवक्ता धनेश सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष बिल्डर्स के विरुद्ध व्यवसायिक कदाचरण का वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आयोग ने बिल्डर्स को दोषी पाते हुए फोरम के सदस्य पंकज देवड़ा द्वारा 24 जनवरी 2024 को परिवादी द्वारा दी गई रकम रूपए 10 लाख को परिवाद प्रस्तुति दिनांक से आदेश दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस करने, मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के एवज में रूपये 10 हजार व्यवसायिक कदाचरण के एवज में 10 हजार एवं वाद व्यय के मद में 5000 रुपए आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर परिवादीनी को दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश सिंह द्वारा की गई।

सिटी सेंटर मॉल हादसा-सीएम साय का निर्देश, प्रदेश के सभी मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर लगे उपकरणों की होगी जांच

रायपुर। राजधानी के शॉपिंग मॉल में हुए हादसे में एक साले के मासूम राजवीर की दु:खद मृत्यु के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल के लिए निर्देश दिया है. अब प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों के सुरक्षा उपकरणों समेत अन्य सुरक्षा व्यवस्था की जांच होगी. इसकी जानकारी सीएम ने के माध्यम से दी है. बता दें कि बीते 19 मार्च को एक परिवार सिटी सेंटर मॉल में दूसरे माले से तीसरे माले में जाने के लिए स्केलेटर में चढ़ रहा था. इसी दौरान एक साल का मासूम युवक के हाथ से छूट गया और वह नीचे जा गिरा. बच्चे को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई.

आमजन, गरीब-मज़लूमों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध क्रांतिकारी पत्रकारिता का नाम है भारत सम्मान, जब शासन-सत्ता में बैठे ऐसे लोग जो पद-पावर के नशे में चूर होकर करते हैं अपने कर्तव्यपालन में चूक तो भारत सम्मान करता है उन्हें दुरुस्त...

2011 से भारत सम्मान आगे बढ़ रहा है और मिसाल क़ायम कर रहा है ईमानदार पत्रकारिता की..

भारत सम्मान दैनिक समाचार पत्र के साथ-साथ वेबसाईट - www.bharatsamman.com, फेसबुक पेज - Bharat Samman व यू-ट्यूब - Bharat Samman News के माध्यम से जनहित के खबरों को प्राथमिकता देते हैं। हमारा दावा है यदि आप पर जुल्म हुआ है, आप न्याय के लिए कर रहे हैं संघर्ष तो केवल एक ही नाम आपको याद होना चाहिए...

भारत सम्मान

इसी क्रांतिकारी मुहिम से निम्न जगहों पर जुड़ने के लिए सम्पर्क करें

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, उतराखण्ड, बिहार, बंगाल व देश के सभी राज्यों में ब्यूरो व संवाददाता बनने संपर्क कर सकते हैं।

इन पदों में होंगे नियुक्त...

1 - राज्य ब्यूरो प्रमुख
2 - राज्य अपराध ब्यूरो प्रमुख
3 - जिला ब्यूरो प्रमुख
4 - जिला अपराध ब्यूरो प्रमुख
5 - तहसील संवाददाता
6 - तहसील अपराध संवाददाता

अपना फोटो लगा बायोडाटा हमारी ई-मेल आईडी bharatsammannews@gmail.com या व्हाट्सएप No. 09303890212 पर भेजे।

नोट

1. केवल ईमानदार लोग ही संपर्क करें, पत्रकारिता के नाम पर वसूली करने अथवा ब्लैकमेल करने वालों से हमारा कोई वास्ता नहीं
2. यहां नौकरी नहीं दी जाती है, यदि हमारे संस्था के नाम का गलत इस्तेमाल करता है, तो हमारे द्वारा जारी नंबर पर शिकायत जरूर करें।

प्रसार/प्रबंध
सम्पादक
भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
094242 62547
09303890212

RNI No. CHHHIN/2011/38292
भारत सम्मान NEWS
अम्बिकापुर, शुक्रवार, 22 मार्च 2024

कलेक्ट्रेट समेत कई कार्यालयों में गैरहाजिर रहे अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर ने सीएमएचओ और ईईओ को थमाया कारण बताओ नोटिस, एक दिन का वेतन काटने के दिए निर्देश

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं संबंधित कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया. कार्यालयीन समय पर अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दिन का असाधारण अवकाश घोषित करते हुए वेतन काटने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय आएं और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए क्रियान्वित करें. यदि भविष्य में कोई अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया तो फिर से कार्यवाही की जाएगी.

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज सुबह 10 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों की उपस्थिति देखी. कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाने पर वहां की पंजी अपने साथ ले आएं. साथ ही कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया. उन्होंने कृषि कार्यालय और कलेक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों का भी निरीक्षण किया.

इस विभागों के कर्मचारी रहे अनुपस्थित

निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग के कुल 27 कर्मचारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कुल 48 कर्मचारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 31 कर्मचारी, जिला मुख्यालय के 8 कर्मचारी, खाद्य शाखा से 8 कर्मचारी, आदिवासी विकास से 2 कर्मचारी, आबकारी शाखा से 1 कर्मचारी, भू-अभिलेख से 1 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. इस पर कलेक्टर डॉ. सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए और एक दिन की असाधारण अवकाश घोषित करते हुए उनके एक दिन का वेतन काटने के लिए वित्त शाखा को निर्देश दिया.

डीजे और मुखौटे पर रहेगा प्रतिबंध, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक ली. बैठक में सभी समाज के प्रमुख नागरिक शामिल हुए. उन्हें होली व अन्य त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए. इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी अपने-अपने सुझाव रखें. इस पर अधिकारियों ने गंभीरता से विचार करने की बात कही. बैठक में नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने कहा कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, जो हम सबके जीवन में खुशियां बिखेरते हुए रंगमय बनाता है. सभी से आग्रह है कि सभी सौहार्द्रपूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ त्यौहार मनाएं. होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर मुरूम की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए जोन आयुक्तों को निर्देशित किया गया है. सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत व्यवस्था एवं साफ-सफाई किए जाएंगे. साथ ही पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाएगी.

बिना अनुमति नए स्थान पर नहीं कर सकेंगे होलिका दहन

अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने कहा कि अस्त्र-शस्त्र के उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा. मुखौटे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. जबरदस्ती चंदा वसूलने पर कार्यवाही की जाएगी. होलिका दहन सड़क किनारे किया जाए और होलिका दहन के बाद रेत डलवाने का कार्य किया जाएगा. लाखेनगर, चांदनी चैक और कुकरी पारा में जिन स्थानों में पूर्व से होलिका दहन किया जा रहा है, उनको छोड़कर नए स्थलों में बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं किया जाएगा.

रात 12:30 बजे तक कर सकेंगे होलिका दहन

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले ने कहा कि होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12:30 बजे तक किया जा सकेगा. इसके बाद नागरिकों को वापस घर भेजे जाएंगे. होली त्यौहार के दौरान आईटीएमएस के जरिए तेज रफ्तार चलाने वाले वाहनों का चिंहाकन किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी. मुखौटा लगाकर घूमने वालों पर भी सख्त कार्यवाही होगी. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी. हुडदंग करने वालों पर भी निगरानी रखी जाएगी. किसी भी तरह का अशांति फैलाने पर भी कार्यवाही होगी. इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे.

पांच दिनों में चार डिग्री बढ़ेगा तापमान, 12.8 डिग्री के साथ अंबिकापुर सबसे ठंडा

रायपुर। बारिश व ओले गिरने के चलते बीते दो दिनों से आ रही मौसम की ठंडकता के बाद अब प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। अगले पांच दिनों में चार डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।

गुरुवार को प्रदेश में अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा,यहां का न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही रायपुर का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम व न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम रहा। गुरुवार को रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा।

ठंडी हवाओं के चलने के कारण दोपहर की धूप भी थोड़ी राहत भरी रही। हालांकि आने वाले दिनों में अब गर्मी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार होली के दौरान फिर से गर्मी बढ़ सकती है। गुरुवार को रायपुर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे। बिलासपुर में तो अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री कम रहा। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि इन दिनों दक्षिण से आने वाली हवाएं थोड़ी कम रही है,इसके चलते अब मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा।

बयाना लेकर रजिस्ट्री नहीं करवाया, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

रायपुर। बैंक से लोन लेकर 17 लाख रुपए बयाना लेकर रजिस्ट्री नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर मोवा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी वंदना गर्ग अविनाश केपिटल होम्स सड्डू का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी जयमाला अग्रवाल 57 वर्ष ने लकजोरा एंड एज व्यवसायिक परिसर मोवा स्थित दुकान नंबर 13 के नाम से बैंक से लोन लिया था। जिसकी जानकारी दिए बगैर प्रार्थी को बेचने के लिए सौदा तय कर लिया और 17 लाख रुपए बयाना ले लिया। जब प्रार्थी रजिस्ट्री के लिए बोला तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दिया। जब प्रार्थी को इस बात जानकारी हुई तो उसने इसकी शिकायत मोवा थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

बारिश के साथ गिरे ओले, बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता

बलरामपुर,धमतरी। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम की वजह से कई जगह आंधी-तुफान से साथ भारी बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हुई है. बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल को नुकसान हुआ है. जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. वहीं बलरामपुर जिले में अचानक मौसम बिगड़ने से तूफान के साथ जमकर ओले बरसे. ओलावृष्टि का एक वीडियो भी वाड्रफनगर विकासखंड से आया है, जहां जमकर ओले गिरे. लगभग आधे घंटे तक बारिश और ओला गिरने से मौसम का मिजाज ठंडा हो गया है. बेमौसम बारिश से गेंहू, सरसों और सब्जियों की खेती पर बुरा असर पड़ सकता है. खराब मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है.

धमतरी में भी ओलावृष्टि से फसल हुए बर्बाद *- वहीं धमतरी के माडम सिल्ली इलाके के 6 गांवों में अति ओलावृष्टि हुई है. इतनी ज्यादा बर्फबारी के बाद इलाका ठंड पड़ गया है. कुछ जगहों पर तो बच्चे बर्फ से खेलते भी दिख रहे है. लेकिन ये खूबसूरत लगने वाला दृश्य किसानों के लिए दुखदाई है. इलाके में लगाई गई धान और सब्जी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है. आम, पपीता के पेड़ों पर कुछ बचा नहीं है. बर्फ के इतने बड़े-बड़े गोले बरसे है कि बड़ी संख्या में पक्षी और गिलहरी इनकी चपेट में आकर मर गए हैं. अब क्षेत्र के ग्रामीण प्रशासन से मुआवजा मांग रहे हैं. किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल लगाई थी. जो बर्बाद हो गई है. इस मामले में धमतरी कलेक्टर ने बताया कि राजस्व की टीम को नुकसान का आंकलन करने भेजा गया है.जैसे ही रिपोर्ट आएगी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

अवैध लकड़ी के भंडारण पर कार्रवाई, तहसीलदार ने पेड़ों के गोले जब्त कर वन विभाग को किया सुपुर्द

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अभनपुर के मार्गदर्शन में तहसीलदार नवापारा ने आज अवैध लकड़ियों के भंडारण पर कार्रवाई की है. ग्राम दुलना में रामशरण के ब्यारा में लगभग 800 ङ्क 900 अर्जुन और बंबूल लकड़ी के छोटे बड़े गोले जब्त कर वन विभाग नवापारा को सुपुर्द किया. इसके अलावा ग्राम तर्री के माखन आरा मिल के पीछे रिक्त स्थान से लगभग 200 अर्जुन, सिरसा और बंबूल लकड़ी के छोटे बड़े गोले जब्त कर वन विभाग को सुपुर्द किया.

ग़ौररलब है कि विगत दिनों लगातार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को स्थानीय लोगों से शिकायत प्राप्त हो रही थी. इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आज राजस्व अमला मौक़े पर पहुंची थी. जांच के बाद पाया गया कि अवैध लकड़ियों का भंडारण किया गया है, जिस पर तत्काल कार्यवाही की गई. तहसीलदान ने कहा, यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी.

साय सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मंत्री लखन लाल ने गिनाई उपलब्धियां

कोरबा। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए धमकी देने संबंधित नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर पलटवार भी किया. मंत्री देवांगन ने कहा, कोरबा से कांग्रेस हार रही है इसलिए बौखलाए हुए हैं. भाजपा में पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जयसिंह अग्रवाल डामर चोर है. बीजेपी ऐसे लोगों को जगह नहीं देती. उसके कई आपराधिक मामले हैं.

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक जितेन्द्र जायसवाल द्वारा जायसवाल प्रिंटिंग प्रेस राघवपुरी, डीगमा, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एवं मुद्रित। संपादक जितेन्द्र जायसवाल। मो.नं.-09424262547